साम्राज्यवाद का एक और अस्त्र-विनाशक जीन

• दीपक पाण्डे

पूंजीवादी विकास केवल मानवता के लिए ही विनाशक नहीं साबित होता। बाजार और मुनाफे की अन्धी होड़ से प्रकृति भी अछूती नहीं रही है। दुनिया में पूंजीवादी लूट के चार सौ से अधिक वर्षों के इतिहास में मानव समाज की त्रासद गाथाओं के समान्तर प्रकृति की विनाश-यात्रा भी जारी रही है जो भूमण्डलीकरण के वर्तमान दौर में तेजी के साथ अन्धी गली की ओर अग्रसर है।

पूंजीवाद के लिए समाज और प्रकृति में उपलब्ध हर चीज--मानव श्रम, समस्त कलात्मक एवं वैज्ञानिक उपलब्धियाँ एवं समस्त प्राकृतिक संसाधन बाजार एवं मुनाफे की सेवा के लिए हैं। इससे अधिक कुछ नहीं। किसी कलाकार या वैज्ञानिक के मानवीय सरोकारों से बाजार को कुछ लेना-देना नहीं होता। पूंजीवादी विकास का समूचा इतिहास इस बात का गवाह है कि किस तरह कोई वैज्ञानिक सृजनात्मक भावना और मानवीय सरोकारों से प्रेरित होकर कोई आविष्कार करता है, परन्तु पूंजीवादी समाज की नियंत्रणकारी शक्तियों ने उसका उपयोग विध्वंस के लिए किया। परमाणु ऊर्जा का आविष्कार इसका ज्वलन्त उदाहरण है।

जैव तकनीक के इस नये आविष्कार में, जिसे टर्मिनेटर टेक्नॉलाजी कहा गया है, अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के तहत किसी भी प्रजाति के बीज में 'लेट एम्ब्रियोजिनेसिस एबॅण्डेण्ट जीन' का प्रतिरोपण करके उसे प्रजनन में अक्षम बना दिया जायेगा। जो भी किसान इन प्रजातियों की खेती करेगा वह हर फसल में बीज कम्पनियों से खरीदने के लिए बाध्य होगा। अनुमान है कि सन् 2000 तक अमेरिकी बीज कम्पनी 'मोनसेंटो' समूची दुनिया में इसकी बिक्री शुरू कर देगी।

हालांकि, पूँजीवाद के आरम्भिक दौरों में इस बात की गुंजाइश फिर भी बनी हुई थी कि बाजार में तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र प्रतियोगिता के कारण वैज्ञानिकों के मानवीय सरोकार, बाजार के माध्यम से ही सही, काफी हद तक सृजनात्मक कार्यों में फलीभूत हो जाते थे। लेकिन, बीसवीं सदी के आरम्भ से, एकाधिकारी वित्तीय पूंजी जब से सर्वशक्तिमान सत्ता बनकर पूंजीवादी समाज की नियामक शक्ति बनी है, तब से यह गुंजाइश लगातार कम होती गयी है।

साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण के मौजूदा दौर में, इस वित्तीय पूँजी ने जिस तरह समूचे आर्थिक-राजनीतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन को अपने ऑक्टोपसी पंजे में जकड़ लिया है, अब तो यह गुंजाइश लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। आज तो वित्तीय पूंजी के शहंशाह अपने मुनाफे की हवस शान्त करने के लिए प्रायोजित शोध और आविष्कार करवाते हैं और उसकी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिकों को खरीदकर आधिकारिकता का ठप्पा लगवाते हैं। ऐसे ही अनेकानेक आविष्कारों में एक आविष्कार है, विनाशक जीन अर्थात 'टर्मिनेटर जीन'।

समूची दुनिया में कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन पर अपना एकाधिकार जमा चुकीं कुछ गिनी-चुनी भीमकाय राष्ट्रपारीय कम्पनियां (Trans-national corporation) अपने अतिलाभ (Super Profit) के लिए जो तरह-तरह के हथकण्डे अपनाती हैं, विनाशक जीन भी उन्हीं में से एक है। विगत 3 मार्च 1998 को अमेरिकी पेटेण्ट संख्या 5,72,3765 के तहत स्वीकृत इस आविष्कार को अमेरिका सहित 75 देशों में स्वीकृत के लिए प्रस्तुत किया जा चुका है। इस तकनीक का विकास अमेरिकी कृषि विभाग तथा अमेरिका की ही 'डेल्टा एण्ड पाइन लैण्ड कम्पनी' (यह दुनिया में कपास के बीजों का व्यापार करने वाली सबसे बड़ी कम्पनी है) ने मिलकर किया है। इस शोध पर कुल 7.2 लाख अमेरिकी डालर खर्च हुए हैं।

जैव तकनीक के इस नये आविष्कार में, जिसे टर्मिनेटर टेक्नॉलाजी कहा गया है, अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के तहत किसी भी प्रजाति के बीज में 'लेट एम्ब्रियोजिनेसिस एबॅण्डेण्ट जीन' का प्रतिरोपण करके उसे प्रजनन में अक्षम बना दिया जायेगा। जो भी किसान इन प्रजातियों की खेती करेगा वह हर फसल में बीज कम्पनियों से खरीदने के लिए बाध्य होगा। अनुमान है कि सन् 2000 तक अमेरिकी बीज कम्पनी 'मोनसेंटो' समूची दुनिया में इसकी बिक्री शुरू कर देगी।

इस टर्मिनेटर टेक्नॉलाजी के आविष्कार की आवश्यकता साम्राज्यवादी मुनाफाखोरों को किसलिए पड़ी, इसकी कहानी उनकी मुनाफे की अन्धी हवस की कहानी है। दरअसल, हुआ यह कि 1985 में डॉ० कैनेथ हिबर्ट द्वारा ऊतक संवर्द्धित मक्के के बीज तथा पौधे का पेटेण्ट (260 विशिष्ट लक्षणों के साथ) प्राप्त कर लेने के बाद बीज कम्पनियों के बीच पेटेण्ट प्राप्त करने की होड़ मच गयी। क्योंकि, पेटेण्ट किये गये बीजों को खरीदकर बोआई तो कोई कर सकता है किन्तु उसे दोबारा बोने का अधिकार कम्पनी को इसके एवज में रॉयल्टी भुगतान करने पर ही मिल सकता है। लेकिन, इसमें भी बीज कम्पनियों को अपना मुनाफा पूरी तरह निरापद नहीं नजर आ रहा है। एक तो, पेचीदे पेटेण्ट कानूनों के अमल और रॉयल्टी भुगतान के पचड़े थे और साथ ही इसके अमल के प्रति भी वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। दूसरे, समूची दुनिया में बीजों के पेटेण्ट को लेकर किसानों और तमाम जनपक्षधर बुद्धिजीवियों ने कई स्तरों पर व्यापक विरोध-अभियान छेड़ रखा था। इन वजहों ने बीज कम्पनियों को प्रेरित किया कि वे दुबारा बीजों का बनना ही रोक दें। 'विनाशक जीन' इसी आवश्यकता से उत्पन्न आविष्कार है।

तमाम साम्राज्यवादी देशों, खासकर अमेरिका की राष्ट्रपारीय कम्पनियां अपने इस नये अस्त्र के आविष्कार के साथ और अन्य आर्थिक-राजनीतिक चालबाजियों के जरिये इसकी जीतोड़ कोशिश कर रहीं हैं कि विश्व के कृषि बाजार को अपना बन्धक बनाकर अपने अतिलाभों को बढ़ाते जायें। विशेषकर, उनकी ललचायी निगाहें, भारत सहित तीसरी दुनिया के तमाम गरीब मुल्कों के प्राकृतिक संसाधनों एवं करोड़ों उपभोक्ताओं वाले विशाल बाजार पर गड़ी हुई हैं। पहले 'गैट' के तहत और अब उसके बदले रूप विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू०टी०ओ०) के कन्धों पर सवार होकर ये कम्पनियां विश्व व्यापार को अपने अनुकूल ढाल रहे हैं। भारत सहित तमाम गरीब देशों का शासक पूंजीपति वर्ग अपने स्वार्थों के कारण अपनी-अपनी सरकारों के माध्यम से इसमें पूरी मदद कर रहा है। भारत में, विगत लगभग एक दशक से नयी आर्थिक नीतियों, 'निजीकरण', 'उदारीकरण' के नाम पर यही प्रक्रिया चल रही है जिस पर किसी भी चुनावबाज पार्टी या गठबन्धन को कोई ऐतराज नहीं है। वैसे, भारत में इन नीतियों का अमल आज वहां पहुंच चुका है कि मौजूदा पूंजीवादी ढांचे में अब इसे उलटना सम्भव ही नहीं रह गया है। अटल विहारी बाजपेयी और उनकी सरकार के वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा सहित कई मंत्री बार-बार स्वयं इन नीति को "अपरिवर्तनीय" बता चुके हैं।

कृषि क्षेत्र की ये राष्ट्रपारीय कम्पनियां अब तेजी से इन प्रयासों में जुटी

हुई हैं कि विश्व व्यापार संगठन के कानूनों के प्रभावी रूप से लागू होने के पूर्व इन गरीब देशों के बाजार पर अच्छी तरह कब्जा जमा लें। इसके लिए वे तरह-तरह के नये-पुराने एकाधिकारी हथकण्डे अपना रही हैं। जैसे—देशी बड़ी कम्पनियों में 25-49 प्रतिशत तक शेयर खरीदना, छोटी कम्पनियों का पूर्ण स्वामित्व खरीदना, इन देशों के विश्वविद्यालयों व शोध संस्थानों में अपने हितों के अनुकूल प्रयोगों को प्रायोजित कराना, देशी कम्पनियों के स्वामियों को अन्य कई प्रकार के प्रलोभन देना तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बीज तथा कृषि रसायन उद्योग से जुड़ी कम्पनियों का अपने में विलय (Merger) कर लेना या दूसरे शब्दों में कहें तो हड़प जाना।

इन कम्पनियों को अपने प्रयासों में काफी महत्वपूर्ण सफलताएं भी मिल रही हैं। तीसरी दुनिया के देशों के व्यापार सम्बन्धी नियमों को ढीला करवाने में वे कामयाब होते जा रहे हैं। इसके साथ ही, इन देशों के किसानों की अशिक्षा, पिछड़ेपन और नाजानकारी का फायदा उठाते हुए उनके खेतों तक अपनी पहुंच बनाने की राह भी काफी आसान साबित हो रही है।

'मोनसेण्टो' कम्पनी भारत में कृषि-रसायन व्यवसाय में पहले ही उतर चुकी थी। अब यह भारत में बीज-व्यवसाय में भी पूरी तैयारी के साथ उतर चुकी है। ('टर्मिनेटर टेक्नॉलाजी के विश्व-व्यापी व्यापार का अधिकार 'मोनसेण्टो' के पास ही है।) शुरुआत में यह गेहूं, कपास, मक्का, सूर्यमुखी तथा ज्वार के बीजों का व्यवसाय करने वाली है। इस कम्पनी ने भारत में सूर्यमुखी, बाजार तथा ज्वार की सबसे बड़ी उत्पादक कम्पनी-'कारगिल इण्डिया' को खरीद लिया है। साथ ही इसने भारत की सबसे बड़ी बीज कम्पनी 'महिको' की 26 प्रतिशत शेयर पूंजी लगभग दुगुनी कीमत देकर खरीद लिया है, ताकि इसके देशव्यापी नेटवर्क का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सके।

इतना ही नहीं करोड़ों किसानों को अपने जाल में फंसाने के लिए कई छल-प्रपंचों का सहारा लिया जा रहा है। अपनी खतरनाक तकनीकों और नीतियों के प्रसार के लिए बीज व्यवसाय के देशी 'पुरोधाओं' को समर्थन में खड़ा किया जा रहा है। जैसे 'महिको' के पूर्व अध्यक्ष श्री बी.आर. बारवाले को कम्पनी के मालिकाने से हाथ धो लेने के बाद एक अमेरिकी फाउण्डेशन द्वारा 'विश्व खाद्य पुरस्कार' दिया जाता है तथा अमेरिका की 'क्राप साइंस सोसाइटी श्री बारवाले को 'भारतीय बीज उद्योग जगत का जनक' की उपाधि से विभूषित करती है। इन पुरस्कारों से कृतज्ञ बारवाले भारत में 'टर्मिनेटर जीन' के परीक्षण को उचित ठहराते हैं। यह वही चिरपरिचित हथकण्डा है जिसके तहत साम्राज्यवादी सरपरस्ती के सामने नतमस्तक होने वालों को भारतीय समाज में नायकों की तरह स्थापित किया जाता रहा है।

इस विनाशकारी टर्मिनेटर तकनीक द्वारा भारतीय कृषि को अपने कब्जे में कर लेने के बाद हालात यह होंगे कि किसान खेतों के मालिक तो होंगे लेकिन वे क्या और कैसे बोयेंगे, इस पर सुदूर बैठी बीज एवं कृषि रसायन कम्पनियों का अधिकार होगा। इस तरह, सदियों से पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही किसानों की अपनी 'बीज-संस्कृति' के पूर्ण विलोपन का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा। 1947 के बाद देश की किसान आबादी की जीवन-शैली पर बाजार के दबाव लगातार बढ़ते ही गये थे, फिर भी अभी तक इस दबाव के बावजूद एक उत्पादक के रूप में वह एक तुलनात्मक स्वायत्तता अनुभव करती थी। अब यह चीज जिस रूप में भी बची हुई थी, अपना अस्तित्व खो बैठेगी।

यह विनाशक 'जीन' तकनीक इतना ही नहीं करेगा। इसके कुछ दूरगामी परिणाम ऐसे हैं कि उनके प्रभावों को मिटाने में आने वाली पीढ़ियों की अकूत मानसिक-भौतिक ऊर्जा इसमें खप जायेगी। सम्भावना इस बात की है कि पर-परागित फसलों में परागकणों द्वारा यह 'जीन' दूसरे पौधों में भी स्थानान्तरित हो सकता है, जिससे उन फसलों के बीज भी बाँझ हो जायेंगे और किसान के लिए बेकार हो जायेंगे। इससे सर्वाधिक खतरा फसलों की पारम्परिक प्रजातियों को हो सकता है जो पूरी तरह नष्ट हो सकती हैं। साथ ही, कुछ जंगली पौधों की प्रजातियाँ भी नष्ट हो सकती हैं जिससे नयी पौध-प्रजातियों के विकास पर प्रश्न चिह्न खड़ा हो जायेगा। संक्षेप में इस विनाशक तकनीक ने भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों की समूची समृद्ध जैव-विविधता (Bio-diversity) को ही विनाश के मुंह में धकेल दिया है।

इन राष्ट्रपारीय निगमों के बीजों एवं कृषि रसायनों का इस्तेमाल करने वाले किसानों पर क्या बीतेगी इसका संकेत हमें पहले ही मिल चुका है। कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों द्वारा नयी प्रजातियों की महंगी खेती से कर्ज के मकड़जाले में फंसने के कारण पिछले वर्ष गहरी हताशा की मनःस्थिति में की गयी सामूहिक आत्महत्याएं तो शुरुआत भर हैं और भी बड़ी त्रासदियों की। मुनाफे के लिए खेती करने वाले पूंजीवादी भूस्वामी-फार्मर तो बर्बादी से खुद को बचा ले जायेंगे, लेकिन छोटे-मंझोले किसानों के लिए, जो अपनी जिन्दगी की गाड़ी खींचने के लिए मुख्यतः खेती पर निर्भर हैं, बर्बादी का एक नया सफर शुरू होगा।

इस प्रकार बीजों के क्षेत्र में परमाणु बम से भी खतरनाक स्थिति पैदा कर ये राक्षसी राष्ट्रपारीय कम्पनियां अपने साम्राज्यवादी मंसूबों को पूरा करने में जुटी हुई हैं। हमारे देश के पूंजीपति इस साम्राज्यवादी लूट में जूनियर पार्टनर बनकर सहयोगी भूमिका निभा रहे हैं और सरकार एवं संसद-विधानसभाओं में बैठे उनके राजनीतिक चाकर इस विनाशक-मार्ग के तमाम अवरोधों को हटा रहें हैं।

देश का समूचा मेहनतकश अवाम एक नये किस्म की आर्थिक-राजनीतिक-सांस्कृतिक-नैतिक गुलामी के गर्त में धकेला जा रहा है। कौन रोकेगा इसे?

इस सवाल के जवाब के लिए आज सारा समाज छात्रों-युवाओं की ओर उम्मीदें टिकाये हुए है। इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए छात्रों-युवाओं को यह भलीभांति समझना होगा कि पूंजीवाद-साम्राज्यवाद का समूल नाश ही एकमात्र मार्ग है। बाजार एवं मुनाफा केन्द्रित सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के स्थान पर श्रम केन्द्रित एवं मानव केन्द्रित नयी समाजवादी व्यवस्था ही प्रकृति और समाज को विनाश के मुंह से बाहर निकाल सकती है। इतिहास की कार्यसूची पर एक फौरी कार्यभार के रूप में दर्ज हो चुके इस लक्ष्य को मेहनतकश अवाम के साथ मिलकर नौजवानों को ही पूरा करना है। •

शुभकामनाओं सहित :

मॉं गायत्री ट्रेडर्स

गवर्नमेण्ट एवं इंस्टीट्यूशनल सप्लायर

सीमेण्ट एवं गिट्टी

के थोक एवं फुटकर विक्रेता

निकट फातिमा अस्पताल, बाई पास रोड,
शिवपुर शहबाजगंज, गोरखपुर